एआई से सेमीकंडक्टर तक, यूपी में तकनीकी विकास की नई उड़ान

यूपी के 5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर, वैश्विक स्तर की कंपनियों में काम करने का मौका

नीयत, नीति और नतीजा

उत्तर प्रदेश में एक दशक पहले की बात करें तो आईटी क्षेत्र में ऐसा शून्य दिखाई देता था, जिसके भरने की उम्मीद तक न दिखाई देती थी। न कोई ठोस नीति थी, न निवेशकों का भरोसा और न ही वह बुनियादी ढांचा जो किसी बड़े तकनीकी बदलाव की नींव रख सके। हर साल बड़ी संख्या में इंजीनियर डिग्री लेकर निकलते, लेकिन राज्य के पास उन्हें रोकने के लिए ठोस अवसर नहीं थे। तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं का बाहर जाना मजबूरी थी लेकिन अब यह परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने खुद को आउटसोर्सिंग केंद्र से आगे बढ़ाकर एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप-टेक और सेमीकंडक्टर जैसे उन्नत क्षेत्रों में स्थापित करने की रणनीति पर अमल किया और परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हाल में मुख्यमंत्री की बेंगलुरु यात्रा के दौरान 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते इसी नीतिगत निरंतरता का परिणाम हैं।

नीयत ने खत्म किया भरोसे का संकट

2017 से पहले प्रदेश का आईटी क्षेत्र मुख्यतः कॉल सेंटर और बीपीओ तक सीमित था। अनुसंधान, उत्पाद विकास और साइबर सुरक्षा जैसे उच्च-स्तरीय कार्य लगभग अनुपस्थित थे। इसके पीछे कारण नीतिगत नहीं, बल्कि प्रशासनिक और भरोसे का संकट था। सरकार ने सबसे पहले इसी संकट को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए और कानून-व्यवस्था को मजबूत कर अनुपालन प्रक्रियाओं को इतना सरल बनाया कि किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। 'निवेश मित्र' पोर्टल के जरिए 43 विभागों की करीब 490 सेवाओं को एक मंच पर लाना इसी सोच का हिस्सा था कि जब तक प्रशासनिक ढांचा भरोसेमंद नहीं होगा, तब तक कोई भी उद्योग-नीति सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह जाएगी। सरकार की यही नीयत आगे चलकर जीसीसी नीति-2024 जैसे बड़े कदमों का आधार बनी।

स्पष्ट विजन, तकनीकी क्षमता के निर्माण पर केंद्रित हुई नीतियां

प्रदेश सरकार की रणनीति केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। इसी सोच के तहत राज्य में सात सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए, जहां एआई, ब्लॉकचेन, 5जी और 6जी जैसी तकनीकों पर प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं दी जा रही हैं। लखनऊ में 20 एकड़ से अधिक भूमि पर प्रस्तावित देश की पहली 'एआई सिटी' इस दृष्टिकोण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। इसका लक्ष्य एआई आधारित उद्योगों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों के लिए एक स्वतंत्र इकोसिस्टम तैयार करना है, न कि सिर्फ किसी एक परियोजना को खड़ा करना। इसे राज्य के दीर्घकालिक 'डीप टेक कैपिटल' बनने के लक्ष्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिसमें तकनीक सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि आर्थिक नीति का केंद्रीय स्तंभ है।

आत्मनिर्भरता की नींव है डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर

डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है, और यहीं उत्तर प्रदेश की नीति सबसे ठोस नजर आती है। गाजियाबाद के सीईएल परिसर में 30 मेगावाट क्षमता का ग्रीन डेटा सेंटर स्मार्ट कूलिंग और रेनवाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों पर आधारित होगा, जबकि सरकार 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश से आठ डेटा सेंटर पार्क विकसित कर रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अब उत्तर भारत के प्रमुख डेटा सेंटर क्लस्टर बन चुके हैं। इसी क्रम में देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का 55 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण अब उत्तर प्रदेश में होता है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एचसीएल-फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम से बन रही 3,700 करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर यूनिट और 'सेमीकंडक्टर नीति-2024' घोषित करने वाला देश का चौथा राज्य बनना एक बड़ी उपलब्धि है और इससे यह संदेश भी मिलता है कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की व्यापक नीतिगत दिशा की ओर बढ़ रहा है।

जीसीसी नीति-2024: निवेश से रोजगार तक का खाका

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वे केंद्र होते हैं जो अनुसंधान, सॉफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा और वित्तीय संचालन जैसे कार्य संभालते हैं। उत्तर प्रदेश की जीसीसी नीति का ढांचा दो श्रेणियों में बंटा है। लेवल-1 जीसीसी के लिए गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में न्यूनतम 20 करोड़ रुपये निवेश या 200 रोजगार, अन्य जिलों में 15 करोड़ या 100 रोजगार अनिवार्य है। एडवांस्ड जीसीसी के लिए यह सीमा क्रमशः 75 करोड़/500 रोजगार और 50 करोड़/300 रोजगार तय की गई है। इस वर्गीकरण नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बड़े और मंझोले निवेशकों, दोनों को समायोजित करता है और भौगोलिक असंतुलन को रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में भूमि सब्सिडी 50 प्रतिशत तक रखी गई है, जबकि गौतमबुद्धनगर-गाजियाबाद में यह 30 प्रतिशत है। पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी, परिचालन व्यय पर 20 प्रतिशत सब्सिडी, पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी में पूर्ण छूट जैसे प्रावधान नीति को वित्तीय रूप से भी प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

अवसंरचना और कनेक्टिविटी का नया रोडमैप

औद्योगिक नीति की सफलता उसके भौतिक ढांचे पर टिकी होती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सैमसंग, ओप्पो, हायर, एनटीटी, एसटीटी ग्लोबल सहित 200 से अधिक वैश्विक कंपनियां सक्रिय हैं, और माइक्रोसॉफ्ट, योटा, अडानीकॉनेक्स जैसी कंपनियों ने यहां बड़ा निवेश किया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी को मजबूत किया है, जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को वैश्विक कंपनियों के लिए निर्णायक कारक माना जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और रायबरेली को जोड़कर बनाई जा रही उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (यूपी-एससीआर) योजना इस बात का संकेत है कि प्रदेश की तकनीकी नीति अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं, बल्कि टियर-2 शहरों को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

रोजगार और समावेशी विकास का लक्ष्य

नीति का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड रोजगार सृजन है। स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर कंपनियों को प्रति कर्मचारी 20 हजार रुपये तक की सीधी सहायता दी जा रही है, जबकि महिला, एससी-एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए ईपीएफ प्रतिपूर्ति का अलग प्रावधान रखा गया है। इस नीति का लक्ष्य केवल रोजगार वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से समावेशी विकास भी है। 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और मेड-टेक जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर सरकार भविष्य की मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार करने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश की 56 प्रतिशत आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है, और राज्य हर वर्ष करीब 12.75 लाख स्नातक तैयार करता है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार भारत का जीसीसी क्षेत्र 2030 तक करीब 25 लाख रोजगार सृजित कर सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष औपचारिक नौकरियों का लक्ष्य तय किया है। इस रोजगार वृद्धि का असर आईटी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। आवास, परिवहन, रिटेल और सेवा क्षेत्रों में भी इसका विस्तार टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचने की संभावना है।

मीडिया सॉल्यूशन इनीशिएटिव

बेंगलुरू में गत् दिवस आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान करती टीमलीज सर्विसेज की एमडी एवं ग्रुप सीईओ सुपर्णा मित्रा एवं टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा। (फाइल फोटो)